अध्याय – 23

सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था
(Government Budget & Economy)

सरकार की वह क्रिया वित्तीय प्रशासन मानी जाती है जिसके द्वारा सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था, नियन्त्रण एवं प्रबन्धन किया जाता है। वित्तीय प्रशासन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आय को न्याय संगत तरीके से एकत्रित किया जाये और सरकार के व्यय को मितव्ययता पूर्ण ढ़ंग से किया जाये। बजट सरकार की राजस्व नीति का व्यावहारिक रूप होता है। भारत में बजट सामान्यतया आगामी वित्तीय वर्ष हेतु आवश्यक सरकारी खर्च की सुनिश्चिता प्राप्त करने का प्रावधान है।

वित्तीय प्रशासन में बजट महत्वपूर्ण होता है इसे वित्तीय प्रशासन की धुरी कहा जा सकता है सरकार की आय, व्यय और ऋण आदि से सम्बन्धित समस्त क्रियाओं का निर्धारण बजट के माध्यम से होता है।

बजट का अर्थ एवं परिभाषा –

बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द Bougette से मानी जाती है। जिसका तात्पर्य '' चमड़े के थैले ''। 1733 में बजट शब्द का प्रयोग इंग्लैण्ड में 'जादू के पिटारे' के अर्थ में किया गया।

बजट सरकार की आय एवं व्यय का एक विवरण प्रपत्र है जिसमें आगामी वर्ष के लिये आय–व्यय के अनुमानित आकड़े एवं आगामी वर्ष के सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रम तथा आय–व्यय को घटाने–बढ़ाने के लिये प्रस्तावों का विवरण होता है। सामान्यतया बजट का तात्पर्य सरकार के उस विवरण पत्र से होता है जिसमें वर्ष पर्यन्त होने वाले आय–व्यय का ब्यौरा दर्शाया जाता है, व्यापक अर्थ में इसका आशय यह है कि बजट में निहित तथ्यों को उस समय तक गुप्त रखा जाता है जब तक कि उसे देश की संसद के समक्ष प्रस्तुत न कर दिया जावे। विभिन्न विद्वानों ने बजट को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है :–

प्रो. बेस्टेबल (Prof. Bastable) के अनुसार बजट का अर्थ है ''एक दिये गये समय के लिये वित्तीय प्रबन्ध जिसके साथ विधानसभा में स्वीकृति के लिये पेश करने का सामान्य सुझाव जुड़ा हुआ है।''

फिण्डले शिराज के अनुसार ''बजट एक साथ एक रिपोर्ट, एक अनुमान तथा एक प्रस्ताव है। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वित्तीय प्रशासन की सभी विधियों को सम्बन्धित किया जाता है, उनकी तुलना की जाती है एवं समन्वय स्थापित किया जाता है।''

स्पष्ट है कि बजट के दो पक्ष होते हैं। एक ओर सरकार की प्रत्याशित आय जबकि दूसरी और सरकार के प्रत्याशित व्यय को व्यक्त किया जाता है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सरकार प्रतिवर्ष बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है और संसद की स्वीकृति होने के पश्चात इसके प्रस्ताव के अनुसार ही कार्य किये जाते हैं।

बजट के उद्देश्य–

देश की अर्थव्यवस्था को दिशा प्रदान करना बजट का प्रमुख उद्देश्य होता है। देश की अर्थव्यवस्था सरकार के बजट से प्रभावित होती हैं। बजट के प्रमुख मुख्य उद्‌देश्य निम्न है–

1.– सरकारी बजट से न केवल विकास प्रभावित होता है बल्कि विकास की दिशा भी बजट से निर्धारित होती है।

2.– उत्पादन बढ़ानें मे भी बजट की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है बजट में राहत द्वारा दिये गये करारोपण सम्बन्धी रियायतों एवं शुल्क में राहत द्वारा दिये गये प्रोत्साहन उत्पादन वृद्धि में सहायक होते हैं।

3.– सामान्यतया सरकार बजट के माध्यम से नये कर लगाकर और जनता से ऋण लेकर उसकी क्रय शक्ति में कमी करते हुये कीमत स्तर को नियन्त्रित करती है।

4– देश के आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना एवं आय व धन का पुनर्वितरण करना।

5– देश की उत्पादन संरचना एवं उत्पादन के स्तर को दिशा देना। बजट में करारोपण सम्बन्धी रियायतें एवं प्रोत्साहन उत्पादन वृद्धि में सहायक होता है।

6– देश में प्रचलित मुद्रा स्फीति एवं अवस्फीति का उपचार बजट प्रावधानों में परिवर्तन द्वारा किया जाता है। जिससे आर्थिक स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

7– कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य बजट की

सहायता से प्राप्त किया जा सकता है।

8– आर्थिक असमानता पर रोक, सामाजिक सुरक्षा हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन, आर्थिक विकास हेतु योजनाओं का निर्माण बजट के प्रावधानों के माध्यम से ही किये जाते है।

बजट के प्रकार (स्वरूप) :–

सरकारी बजट को सरकारी आय व व्यय की प्रवृत्ति एवं सन्तुलन के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. राजस्व एवं पूँजीगत बजट :–

सरकारी बजट सरकार की आय व व्यय को दर्शाने वाला होता है इसे आय व व्यय की प्रवृति के आधार पर निम्न दो भागों में बाँटा जाता है –

(i) राजस्व बजट **(Revenue Budget)** :– यह बजट के प्रथम भाग में ही दर्शाया जाता है, जिसमें राजस्व आय (Revenue Income) या राजस्व प्राप्तियाँ (Revenue Receipts) प्रदर्शित की जाती है। इन प्राप्तियों को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है –

(i) *राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय* **(Revenue Reciepts & Revenue Expenditure) :–**

इसके अन्तर्गत वह आय दर्शायी जाती है, जिसका सम्बन्ध उसी वित्तीय वर्ष से होता है, इसे चालू खाता भी कहा जाता है। इस खाते में आय के वे स्त्रोत शामिल होते हैं जिनके बदले में कोई भुगतान नहीं करना होता है जैसे– करों से प्राप्त आय, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ, सरकारी उद्योग पर प्राप्त ब्याज आदि।

राजस्व बजट के अन्तर्गत राजस्व आय एवं राजस्व प्राप्तियाँ दर्शायी जाती है। राजस्व आय एवं राजस्व प्राप्तियों में (अ) कर राजस्व – जैसे आयकर, निगम कर, सम्पत्ति कर, उपहार कर, शास्ति कर उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, व्यय इत्यादि आते हैं। (ब) गैर कर राजस्व – में ऋृण, ब्याज, शुल्क, शास्ति, जुर्माना इत्यादि आते हैं।

राजस्व व्यय को बजट में गैर विकासात्मक व्यय, तथा विकास व्यय के रूप में विभाजित किया जाता है। गैर विकासात्मक व्यय के अन्तर्गत सरकारी सेवाओं पर व्यय, सरकारी सब्सिडी, सरकारी अनुदान एवं ब्याज की अदायगी शामिल है जबकि विकासात्मक व्यय के अन्तर्गत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, कृषि एवं सहायता सेवाओं, उद्योग–खनिज, उर्वरक सब्सिडी सामान्य आर्थिक सेवाये, विद्युत सिचाई, बाढ़ नियन्त्रण, सार्वजनिक निर्माण, परिवहन एवं संचार, राज्यों को अनुदान को शामिल किया जाता है।

राजस्व व्यय को भी दो भागों में दर्शाया जाता है। (अ) आयोजना भिन्न व्यय– राजस्व खाते से (ब) आयोजना व्यय–राजस्व खाते से। इन दोनों मदों में सरकारी बजट के आयोजना एवं आयोजना भिन्न मदों में होने वाले व्यय को दर्शाया जाता है।

(अ) कर राजस्व (Tax Revenue)

(ब) गैरकर राजस्व (Non Tax Revenue)

बजट में राजस्व प्राप्तियों के बाद अगले भाग में राजस्व व्यय दर्शाया जाता है। राजस्व व्यय को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है।

(अ) आयोजना भिन्न व्यय–राजस्व खाते से (Non plan Expenditure in revenue Account)

(ब) आयोजना व्यय – राजस्व खाते से (Plan Expenditure in Revenue Account)

(ii) पूँजीगत बजट **(Capital Budget)** –

बजट दस्तावेज के दूसरे भाग में इसे दर्शाया जाता है जिसके दो भाग –

(ii) *पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं पूँजीगत व्यय* **(Capital Reciepts & Capital Expenditure) :–**

इसके अन्तर्गत आय के उन समस्त स्त्रोतों को रखा जाता

राजस्व बजट		पूँजीगत बजट	
प्राप्तियों की मदें	व्यय की मदें	प्राप्तियों की मदें	व्यय की मदे
– कर आय – लाभ व लाभांश – ब्याज आय – गैर कर आय	– सरकारी सेवाओं पर व्यय – ब्याज अदायगी – अनुदान – सब्सिडी – सामान्य आर्थिक सेवायें – सार्वजनिक निर्माण	– निबल घरेलू ऋण – निबल विदेशी ऋण – ऋण वापसी – लोक सेवा प्राप्तियाँ	– परिसम्पत्तियों का निर्माण – संचित कोष – आकष्मिक कोष

है, जिनके बदले में भुगतान करना आवश्यक होता है। पूँजीगत व्यय खाते में उन व्ययों को शामिल किया जाता है, जिनमें व्यय तो चालू वर्ष में दिया जाये किन्तु इससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि चालू वर्ष के साथ–साथ आगामी वर्षों तक होती रहे।

पूँजीगत आय के अन्तर्गत ॠणों की वसूली, विविध प्रकार की प्राप्तियाँ, इत्यादि दर्शायी जाती है, जबकि पूँजीगत व्यय को आयोजना–भिन्न व्यय–पूँजीगत खाते से तथा आयोजना व्यय–पूँजीगत खाते दर्शाया जाता है।

(अ) पूँजीगत प्राप्तियाँ **(Capital Receipts)** – इसके अन्तर्गत ऋणों की वसूली, विविध प्राप्तियाँ, उधार व अन्य देनदारियाँ दर्शायी जाती हैं। इनकी कुल प्राप्तियों का योग पूँजीगत प्राप्तियाँ कहलाती हैं।

(ब) पूँजीगत व्यय **(Capital Expenditure)** – पूँजीगत व्यय को भी दो भागों में बाँटा जाता है। (1) आयोजना भिन्न व्यय–पूँजीगत खाते से (Non Plan Expenditure in capital Acccount) एवं (2) आयोजना व्यय पूँजीगत खाते से (Plan Expenditure in capital Acccount)

2. सरकार की कुल आय एवं कुल व्यय में समानता या अन्तर के आधार पर भी सरकारी बजट के प्रमुख तीन प्रकार निम्न हैं –

(i) बचत का बजट **(Surplus Budget)**

वह बजट बचत का बजट कहलाता है जिसमें सरकार के व्यय की अपेक्षा आय का आधिक्य हो। अर्थात सरकार की कुल आय उसके कुल व्यय की अपेक्षा अधिक हो।

अर्थात कुल आय > कुल व्यय (धनात्मक अन्तर)

(ii) सन्तुलित बजट **(Balanced Budget)**

जिस बजट दस्तावेज मे सरकारी आय व सरकारी व्यय दोनों समान हो तो वह सन्तुलित बजट कहलाता है।

सन्तुलित बजट = कुल आय = कुल व्यय

(iii) घाटे का बजट **(Deficit Budget)**

सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज में सरकारी व्यय की अपेक्षा सरकारी आय कम हो तो उसे घाटे का बजट कहा जाता है। आधुनिक युग में प्रायः सभी लोकतान्त्रिक देशों में सरकार को जनकल्याणकारी कार्यों का निर्वहन हेतु कई प्रकार के व्यय करने पड़ते हैं। आर्थिक विकास की बढती माँग, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर बढ़ता व्यय, देश की माँग बढ़ने से सरकारों का सार्वजनिक व्यय तेजी से बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि घाटे का बजट, बजट की लोकप्रिय अवधारणा है।

घाटे का बजट= सरकार का कुल व्यय > सरकारी की कुल आय

बदलते परिवेश मे बजट के प्रकार

सामान्यतया सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि से सम्बन्धित होता है भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रेल से 31 मार्च तक होता है। अर्थव्यवस्था में बदलती हुयी परिस्थितियों, बढ़ते सरकारी हस्तक्षेप के कारण बजट की प्रक्रिया एवं बजट के स्वरूप में आधुनिक युग मे परिवर्तन हुये हैं, जिन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. आम बजट –

आम बजट को पारम्परिक बजट भी कहा जा सकता है, इसका प्रमुख उद्देश्य विधायिका का कार्यपालिका पर वित्तीय नियन्त्रण स्थापित करना रहा है। इस प्रकार के बजट का प्रमुख उद्देश्य सरकारी खर्चों पर नियन्त्रण करना था न कि तीव्र गति से विकास को प्रेरित करना। इस बजट मे मुख्यतः वेतन, मजदूरी, उपकरण, मशीनें आदि के रूप में किये जाने वाले व्यय तथा विभिन्न मदों से होने वाली आय को प्रस्तुत किया जाता है।

पूरक बजट– यदि बजट में स्वीकृत धनराशि 31 मार्च से पूर्व ही समाप्त हो जाये तो इस स्थिति मे सरकार संसद के सम्मुख पूरक बजट प्रस्तुत करती है और अतिरिक्त धनराशि की माँग की जाती है।

लेखानुदान– पिछला बजट 31 मार्च को समाप्त हो जाता है जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता, इसीलिये सरकार को 1 अप्रेल को अपने खर्चों के लिये नये बजट की आवश्यकता होती है संसद अस्थायी रूप से सरकार को व्यय के लिये अग्रिम धनराशि देती है।

2. निष्पादन बजट –

कार्य के परिणामों या निष्पादन को आधार बनाकर निर्मित किया गया बजट निष्पादन बजट कहलाता है। निष्पादन बजट को व्यापक कार्यवाही का दस्तावेज माना जाता है। जो कार्यक्रमों, परियोजनाओं से सम्बन्धित संख्यात्मक आँकड़ो एवं क्रियान्वयन की उपलब्धियों का मापन करता है। यह बजट मूलतः लक्ष्योन्मुखी एवं उद्देश्य परक प्रणाली पर आधारित है।

3. जीरोबेस बजट :–

जीरोबेस (शून्य आधारीय) बजट का जनक अमरीका के पीटर. ए. पायर को माना जाता है। 1979 में इसे अमेरिका के राष्ट्रीय बजट में राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा अपनाया गया ।

शून्य आधारित बजट प्रणाली व्यय पर अकुंश लगाने की एक तार्किक प्रणाली है इस प्रणाली में विगत व्ययों को आधार नहीं बनाया जाता अर्थात विगत व्ययों को भावी व्यय के लिये तर्क के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। इस प्रणाली में प्रत्येक क्रिया कलाप को शून्य आधार से पुनः औचित्य निर्धारित करना पड़ता है न कि पुराने व्ययों पर नये व्ययों का प्रावधान करना। इस बजट प्रणाली को सूर्यास्त बजट प्रणाली (सनसेट सिस्टम) भी कहा जाता है।

4. आउटकम बजट –

सामान्य बजट की तुलना मे यह एक कठिन प्रक्रिया है

जिसमें वित्तिय प्रावधानों को परिणामों के सन्दर्भ में देखा जाता है। बजट मे मूल्याकंन किये जा सकने वाले भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण इस उद्देश्य से किया जाता है कि बजट के क्रियान्वयन की गुणवत्ता को परखा जाना सम्भव हो सके। आउटकम बजट में कार्य सम्पादन हेतु किसी भी स्तर पर देशी या रूकावट के बजाय निर्धारित धनराशि को सही समय, सही मात्रा में पहुँचाना होता है।

5. जेन्डर बजटिंग –

जेन्डर बजटिंग के माध्यम से सरकार द्वारा महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण से सम्बन्धित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिये प्रतिवर्ष बजट में एक निर्धारित राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रावधान किये जाते है। बजट के प्रावधान पुरूष और स्त्री को अलग–अलग तरीके से प्रभावित करते हैं।

(6) संघीय, प्रान्तीय एवं स्थानीय संस्थाओं के बजट–

संघीय एवं प्रान्तीय सरकार के बजट कार्यकारिणी द्वारा तैयार किये जाते हैं तथा कार्यकारिणी द्वारा पास करवाये जाते हैं तथा इनके क्रियान्वयन का दायित्व भी कार्यकारिणी पर रहता है। स्थानीय संस्थाओं का बजट स्वतन्त्र होता है।

(7) सामान्य एवं संकटकालीन बजट–

सामान्य बजट प्रायः अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति के कार्यों से व्यवहार करते हैं, जबकि संकटकालीन बजट असामान्य या विशेष परिस्थितियों जैसे युद्ध, मन्दी आदि से सम्बद्ध होते हैं। दोनों के उत्तरदायित्व, भागीदारी और क्षमतायें अलग–अलग होती हैं। महिलाओं में अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव, शिक्षा के अवसरों में कमी स्वतन्त्र निर्णय न ले पाना इत्यादि परिस्थितियों के कारण जैन्डर बजटिंग का भारत जैसे विकासशील देश में पर्याप्त महत्व है।

बजट घाटे की अवधारणा :–

आधुनिक युग में लोकतान्त्रिक सरकारों द्वारा प्रस्तुत बजट में विविध प्रकार के बजटीय घाटों को दशार्या जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था के स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है।

प्रो. डाल्टन – एक बजट घाटा पूर्ण है यदि एक दिये गये समय के अन्दर व्यय आय से अधिक है।

विभिन्न अवधारणायें :–

(अ) राजस्व घाटा :–

जब बजट के अन्तर्गत दर्शाये गये कुल राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। तो वह अन्तर राजस्व घाटा कहलाता है। अर्थात् राजस्व घाटा बजट की राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व व्यय के आधिक्य को व्यक्त करता है।

सूत्र :

राजस्व घाटा = राजस्व प्राप्तियाँ – राजस्व व्यय

उदाहरण – कुल राजस्व प्राप्तियाँ 1300 करोड़ – कुल राजस्व व्यय 1700 करोड़

अतः कुल राजस्व घाटा = 400 करोड़ रू.

सूत्र की व्याख्या –

राजस्व घाटा = (कुल कर राजस्व + कुल गैर कर राजस्व) – (राजस्व खाते में आयोजना भिन्न व्यय + राजस्व खातें में आयोजना व्यय)

(ब) राजकोषीय घाटा :–

प्रस्तुत बजट में राजकोषीय घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों, गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों के ऊपर सरकार के कुल व्यय (राजस्व व पूँजीगत व्यय, जिसमें उधार लिये गये शुद्ध ऋणों की राशि भी शामिल होती है) का आधिक्य है। स्पष्ट है कि बजट घाटे में उधार एवं अन्य समस्त देनदारियाँ जोड़ दे तो वह राजकोषीय घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था वर्तमान आर्थिक स्थिति का समग्र दर्पण होता है।

राजकोषीय घाटा = बजटीय घाटा + उधार + समस्त देनदारियाँ

(स) वित्तीय घाटा :–

वित्तीय घाटा, सरकारी कोष की वास्तविक स्थिति को व्यक्त करता है इसके अन्तर्गत बजट घाटे के साथ साथ सरकार की शुद्ध उधारी को भी जोड़ा जाता है।

(द) प्राथमिक घाटा :–

राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटाने के बाद जो राशि शेष बचती है उसे प्राथमिक घाटा कहा जाता है। अर्थात ब्याज की अदायगियाँ राजकोषीय घाटे में से निकाल दी जाये तो प्राप्त शेष को प्राथमिक घाटा कहा जाता है।

सूत्रः

प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज अदायगियां

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सरकारी बजट किसी भी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आधुनिक युग में तो सरकारी बजट सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को न केवल प्रभावित करता है बल्कि अर्थव्यवस्था को दिशा भी प्रदान करता है।

भारत में बजट की नवीन प्रवृतियां–

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये केन्द्र सरकार का बजट प्रस्तुत करते हुये वित्तमंत्री अरूण जेटली ने राजकोषीय प्रशासन की व्यवस्था में सुधार के लिये सरकार के व्यय को योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय में वर्गीकृत करने की प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की है। 2017–18 से यह प्रथा समाप्त हो जायेगी और बजट को केवल राजस्व व्यय व पूँजीगत व्यय के रूप में ही वर्गीकृत किया जायेगा।

2016–17 के बजट में डिजिटल साक्षरता स्कीम, कालेधन

की घोषणा हेतु स्कीम, मेक इन इन्डिया सहित एक भारत–श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा प्रस्तावित की गयी है।

सितम्बर 2016 में हुई भारत सरकार की केबिनेट मीटिंग के निर्णयानुसर अगले वित्तीय वर्ष में रेल बजट को भी अलग से प्रस्तुत नहीं किया जायेगा बल्कि इसे देश के आम बजट में एक मद के रूप में दर्शाया जायेगा।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने 7 मई 2003 को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम FRBA Act पारित किया जिसमें प्रावधान किया गया है कि राजस्व घाटे को शून्य किया जाये।

केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व बटँवारे के मानक तय करने हेतु देश में वित्त आयोग समय–समय पर केन्द्र सरकार को सुझाव देता है। केन्द्र व राज्यों दोनों के राजस्व घाटे को शून्य स्तर पर लाकर राजकोषीय सुदृढ़त्रीकरण का सुझाव तेहरवें वित्त आयोग द्वारा दिया गया। वर्तमान में चौदहवाँ वित्त आयोग (जनवरी 2013 में गठित) वाई. वी. रेड्डी की अध्यक्षता में गठित किया गया है, जिससे प्राप्त रिर्पाट पर 2015 से 2020 तक क्रियान्वयन किया जा सकेगा।

भारतीय संविधान मे प्रतिवर्ष बजट को संसद द्वारा पास कराने की व्यवस्था करने से सरकारी मशीनरी द्वारा किये जाने वाले व्यय के लिये संसद की अनुमति की अनिवार्यता का प्रावधान संसद के नियन्त्रण को सर्वोच्चता प्रदान करता है।

आर्थिक नीति के उपकरण के रूप में बजट –

बजट को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। बजट केवल अनुमानों के प्रस्तावक मात्र ही नहीं बल्कि भूतकाल के अनुभव पर आधारित भविष्य के लिये व्यापक योजना एवं कार्यक्रम है जो सरकार की आर्थिक एवं सामाजिक विचारधारा को प्रकट करता है। बजट सरकार की आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण एवं आवश्यक उपकरण है। बजट राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का अभिन्न अंग है। यह देश में अच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सरकार के हाथों में अच्छा उपकरण है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- राजस्व बजट– इसके अन्तर्गत कर एवं शुल्क आदि से प्राप्त होने वाली सरकारी आय शामिल होती है तथा इनके संग्रह पर किया जाने वाला व्यय भी राजस्व बजट में शामिल होता है।
- पूँजीगत बजट– इसके अन्तर्गत सरकार द्वारा प्राप्त किया गया ऋृण उस पर किया गया व्यय एवं सरकारी परिसम्पतियों से होने वाली आय तथा व्यय शामिल होता है।
- आम बजट एक देश की अर्थव्यवस्था का वार्षिक लेख–जोखा होता है।
- संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व बजट को गुप्त रखा जाता है।
- वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केन्द्र व राज्यों के बीच में राजस्व बँटवारा करना है।
- वर्ष 2017 से रेल बजट को आम बजट में शामिल कर लिया गया है।
- आधुनिक युग में बजट की सर्वाधिक लोकप्रिय अवधारणा घाटे का बजट है।
- राजकोषीय घाटा = बजटीय घाटा +उधार+समस्त देनदारियाँ
- सामान्यतया बजट एक वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तुत किया जाता है।
- जेन्डर बजटिंग का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की जागरूकता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न –

1. सन्तुलित बजट से आशय है–
   (अ) कुल आय > कुल व्यय
   (ब) कुल आय < कुल व्यय
   (स) कुल आय = कुल व्यय
   (द) कुल आय = 0 ( )
2. निम्न में से राजस्व प्राप्ति की मद नहीं है–
   (अ) कर आय (ब) लाभांश
   (स) अनुदान (द) गैर कर आय ( )
3. जनता की क्रय शक्ति में कमी करने हेतु सरकार का प्रमुख उपाय है–
   (अ) करों में छूट देना
   (ब) नये कर लगाना
   (स) सरकारी व्यय में वृद्धि करना
   (द) सब्सिडी देना ( )
4. जिस बजट में विगत व्ययों को आधार नहीं बनाया जाता, वह है–
   (अ) आम बजट (ब) घाटे का बजट

(स) पूरक बजट (द) जीरोबेस बजट ( )

5. संसद में प्रतिवर्ष बजट पास करवाने की व्यवस्था से किसकी सर्वोच्चता सिद्ध होती है–

(अ) राष्ट्रपति (ब) प्रधानमंत्री

(स) संसद (द) वित्तमंत्री ( )

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. राजस्व प्राप्तियों को दो भागों में बाँटा जाता है दोनों भागों के नाम लिखो।
2. राजस्व घाटा ज्ञात करने हेतु सूत्र लिखिये।
3. भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि बताइये।
4. शून्य आधारिय बजट का जनक कौन है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. 'आम बजट' से आपका क्या आशय है?
2. बजट की तुलना जादू के पिटारे से की गयी है क्यो ?स्पष्ट करें।
3. बजट का बजट किसे कहा जाता है ?
4. प्राथमिक घाटे से आप क्या समझते हैं ?
5. यदि एक देश के बजट मे राजस्व घाटा 700 करोड़ रू. एवं कुल राजस्व व्यय 1800 करोड़ रू है तो राजस्व प्राप्तियाँ ज्ञात कीजिये।

निबन्धात्मक प्रश्न –

1. बजट घाटे से आप क्या समझते है?इसकी विभिन्न अवधारणाओं को समझायें।
2. बजट को परिभाषित करते हुये इसके महत्व की विवेचना कीजिये।
3. राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय से आपका क्या आशय है?स्पष्ट कीजिये।
4. बजट से आपका क्या आशय है?जेन्डर बजटिंग को क्यों उपयोगी माना गया है?

उत्तर तालिका

1	2	3	4	5
स	स	ब	द	स